ASC- KLS/1P/3.00

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : सभापति महोदय, इस देश की मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिलने से लेकर अब तक, इतने सालों से न्याय नहीं मिला था। ट्रिपल तलाक के कानून को कई बार ...(व्यवधान)....आप इसको सुनिए। कई बार देश की अलग-अलग अदालतों में इसको चेलैंज किया गया। कई बार इस देश की मुस्लिम महिलाएं व मुस्लिम माता-बहनें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में गईं। ऐसा नहीं है कि देश की अदालत ने पहली बार यह फैसला लिया है, शाहबानो के केस में भी फैसला लिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ....(व्यवधान)... ऐसा नहीं कि आपने इस बार भी विरोध नहीं किया है, अभी आप खड़े हो कर कहोगे। आपके विरोध करने का तरीका अलग है, मगर है विरोध ही। जब इस देश की सरकार, इस देश के प्रधान मंत्री मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए, तो राज्य सभा में इसको रोक दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़। मैंने आपको एलॉउ नहीं किया है। ...(व्यवधान)... जब आपको जवाब देना हो, तब बोलिए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर विरोध नहीं करते हैं, तो हम कल ही लेकर आ सकते हैं। ....(व्यवधान)..... हमें क्या आपत्ति है? हम तो लेकर ही आए थे। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा : महिला आरक्षण बिल लेकर आइए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : महिला आरक्षण बिल आप भी नहीं ला पाए थे।

श्री आनन्द शर्मा : हमने राज्य सभा में पास कर दिया, लेकिन लोक सभा में पेंडिंग है। ...(व्यवधान)... हम समर्थन करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : लोक सभा में पारित नहीं कर पाए थे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं है। पुनिया जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)....आप इतने अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... आपने बोला, बस हो गया। ...(व्यवधान)... पांच लोग खड़े होकर अपनी-अपनी बात बोलें, तो यह कौन सी पद्धति है? विपक्ष के नेता और बाकी सदस्यों को जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप इफेक्टिवली काउंटर करिए, इसमें क्या है?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, इस देश के दिव्यांगों को आजादी से लेकर अब तक 'अपाहिज़' शब्द के अपमानजनक शब्द को झेलना पड़ता था। एक संवेदनशील प्रधान मंत्री की दूरदृष्टि ही थी कि अपाहिज़ की जगह दिव्यांग शब्द को कानूनी जामा पहना कर उनको सम्मान देने का काम किया।

सभापति महोदय, इनके रिजर्वेशन में भी बढ़ोतरी की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एयर पोर्ट हो, हर जगह दिव्यांग को अपमानित न होना पड़े, इस प्रकार की बातें सरकार की ओर से प्रारम्भ की गई हैं।

सभापति महोदय, सगर्भा महिलाएं, जब भी सगर्भा होती थीं, अगर वे काम करती हैं, तो उनके मन में एक चिंता रहती थी कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद उनके लिए

जो छः महीने महत्वपूर्ण होते हैं, उस समय में बच्चे की देखभाल कौन करेगा? किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो, खुद के स्वास्थ्य की चिंता करना, बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करना, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सगर्भा महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 वीक की छुट्टी देकर जच्चा और बच्चा दोनों को मदद देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाकर सरकार के संवेदशील चेहरे को हमारे सामने रखा है।

सभापति महोदय, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार की ओर से लिए गए हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं, जिनको सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती है, बल्कि जनता के साथ मिलकर करने पड़ते हैं। जनभागीदारी से स्वच्छता का संस्कार आज समाज के अंदर एक आंदोलन के रूप में प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि पीढ़ियों तक यह स्वच्छता का संस्कार देश को स्वच्छ रखेगा। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ " के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इनकी जन्म रेश्यो भी बहुत से राज्यों सुधर रही है और बच्चियों का ड्रॉप ऑउट रेश्यो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। हमारा "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" और योग पूरे विश्व में मनाने का प्रस्ताव यूएन ने मान लिया है।

(1Q/LP पर जारी)

LP-SSS/3.05/1Q

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर योग पूरे विश्व के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए काम कर रही है।

सभापति महोदय, डीबीटी की चर्चाएँ होती थीं, लेकिन किसी में साहस नहीं था। इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता था, जिसको न कभी दोनों में से किसी एक सदन ने नोट किया, न कभी देश के मीडिया ने नोट किया। डीबीटी के माध्यम से सारे फायदे डायरेक्ट बैंक एकाउंट में पहुंचाकर जब सरकार ने उसे जाँचा तो पाया कि सरकार के हर साल 57,000 करोड़ रुपये बचे हैं। यह पैसा कहाँ जाता था? मैं यह नहीं कहता कि इसको कोई एक व्यक्ति खा जाता था, मगर व्यवस्था के छिद्रों के कारण लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा ऐसे लोग ले जाते थे, जिनका इस पर अधिकार नहीं है। यह 57,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण बचा है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, नीति आयोग का नया इनिशिएटिव भी आज देश में बहुत सारी नीतियाँ बनाने के काम आ रहा है। मैं मानता हूं कि यह परंपरा आने वाले दिनों में देश को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करेगी।

सभापति महोदय, अभी-अभी जो "खेलो इंडिया" का इनिशिएटिव लिया गया है, जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा है और जो खेलों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रजत पदक और स्वर्ण पदक मुझे इस "खेलो इंडिया" के अंदर दिखाई पड़ते हैं। सभापति महोदय, देश के बच्चों की खेलने की आदत चली गई थी, लेकिन "खेलो इंडिया" इनिशिएटिव ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, 115 पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना है। इस देश में कभी ऐसा नहीं सोचा गया कि कौन-सा जिला पिछड़ गया है, लेकिन यह सरकार पहली बार 115 जिलों को चिह्नित करके, उनके लिए एक विशेष कार्य योजना लेकर आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।

सभापति महोदय, काफी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। ..मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ..(व्यवधान)..

श्री आनन्द शर्मा : आप बोलिए।..(व्यवधान)..

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : पेरिस समझौते में भारत का जो रोल रहा, उसने पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिलाया है। अभी दाओस में प्रधान मंत्री जी का जो उद्घाटन भाषण था, मैं मानता हूं कि यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। सभापति महोदय, आज दुनिया जिस दिशा में जा रही है, प्रधान मंत्री जी ने बहुत विनम्रता से, किसी को भी नीचा दिखाए बगैर, देश कितना बड़ा है और कितनी ऊँचाई पर हम हैं, यह दुनिया को बताने का काम दाओस के अंदर किया है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी बात है। यू.एन. असेम्बली के अंदर के हो या अमरीका की सीनेट के अंदर, उन्होंने समानता के भाव के साथ अमरीका की संसद को जिस प्रकार से संबोधित किया, यह देश को दुनिया में गौरव दिलाने वाली घटना है।

सभापति महोदय, इसरो ने अंतरिक्ष में 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर रिकॉर्ड बनाया है। ..(व्यवधान).. पहले हम एक उपग्रह, दो उपग्रह, तेरह उपग्रह, तीस उपग्रह

तक पहुंचे थे, लेकिन अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह स्थापित करके इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं मानता हूं कि इससे देश के सोचने का स्केल बदलता है। अब देश के युवा की "हम सबसे पहले होने चाहिए" - यह भूख जगी है। देश का स्केल बदलने का काम भी इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, डिज़िटल कनेक्टिविटी और शपथ में सभी सार्क देशों का उपस्थित होना और इस 26 जनवरी को दस के दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का यहाँ होना, मैं मानता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, जब हम इस सरकार में आए, तब हमने भ्रष्टाचार के लिए भी कहा था कि हम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का निष्ठावान प्रयास करेंगे। महोदय, 12 लाख करोड़ के घपलों, घोटालों की सरकार के बाद हमारी सरकार बनी, हमें साढ़े तीन साल हो गए हैं, मगर हमने इस प्रकार का काम किया है कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। हमने कोल ब्लॉक्स की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की, खदानों की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की, स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की और इन तीनों नीलामियों को यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा था, set aside करना पड़ा था। आज हम इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। काला धन के खिलाफ एक सोची-समझी रणनीति के तहत बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है।

(1r/klg पर जारी)

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : सबसे पहला प्रस्ताव कैबिनेट का हमने एसआईटी को बनाने का किया, जिसको कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत भी लटकाया जा रहा था। सारी सूचनाएं एसआईटी को ट्रांसफर कर दी गईं। कई नए कानून बनाए, बेनामी संपत्ति का कानून उसमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने काले धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने का सफल प्रयास किया और जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फायदा हुआ। साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते से जो पैसा, काला धन घूम कर आता था, एक अलग तरीके से आता था, उन संधियों को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। नोटबंदी के कारण भी काले धन पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No party will be allowed to speak for more than the allotted time. Don't worry on that count.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: तीन लाख से ज्यादा शैल कंपनियों को बंद करने का काम भी किया है। सभापति महोदय, अब तक 70 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें आईं, वे द्वंद्व में फंसी रहीं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें किसानों का विकास करेंगी या उद्योगों को बढ़ावा देंगी? क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें गांवों का विकास करेंगी या शहरों का विकास करेंगी? क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें रिफॉर्म करेंगी या कल्याण राज्य की स्थापना करेंगी, विदेश नीति को तवज्ज़ोह देंगी या रक्षा नीति को तवज्ज़ोह देंगी? क्या

ऐसी सरकारें ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे या जन-प्रतिनिधि चलाएंगे? इस सरकार ने किसी भी द्वंद्व में फंसे बगैर यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों का भी विकास हो सकता है, उद्योगों का भी विकास हो सकता है, गांव का भी विकास हो सकता है, शहर का भी विकास हो सकता है, रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, जन-कल्याण के काम भी हो सकते हैं, विदेश नीति भी अच्छे से आगे बढ़ाई जा सकती है और दृढ़ रक्षा नीति को भी लागू किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और जन-प्रतिनिधि नीतियां बना रहे हैं। अनेक प्रकार के द्वंद्वों में से बाहर निकालने का काम इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

सभापति महोदय, मल्टीपार्टीज़ डेमोक्रेसी सिस्टम में स्वाभाविक है कि विपक्ष का दायित्व है कि सरकारों की कमजोर कड़ियों को लोगों के सामने रखे और सरकार अपने किए हुए कामों को लोगों के सामने रखे। इसलिए कई बार सदन की कार्यवाही को देखने वाले लोग पशोपेश में पड़ते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है? बुनियादी ये दोनों प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, मगर लोकतंत्र में सरकार ठीक से चली या नहीं चली, इसका पैमाना क्या हो सकता है? मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में सरकार ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, इसका सबसे बड़ा पैमाना जनादेश हो सकता है। जनादेश ही तय करता है कि सरकार ठीक से चली या नहीं चली। साल 2014 की सरकार आने के बाद हरियाणा में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी हारी। महाराष्ट्र में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। झारखंड में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। जम्मू-कश्मीर में चुनाव आया, हम जीत कर आए,

कांग्रेस की सरकार गई। ...(व्यवधान)... बिहार और दिल्ली में चुनाव आए, हमारी सरकार नहीं आई, मगर हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। असम में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, सपा-कांग्रेस हारी, भाजपा जीती और अभी-अभी गोवा में भी चुनाव हुआ, हम फिर से एक बार जीत कर आए हैं। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए। अभी-अभी गुजरात में भी चुनाव आया। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: सभापति महोदय, गुजरात में भी चुनाव आया, 22 साल के बाद फिर से एक बार पांच साल के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ...(व्यवधान)... हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस गई। सभापति महोदय, अब कुछ लोगों को हार में भी जीत दिखाई पड़ती है। अब हम क्या करें? इसका हमारे पास रास्ता ही नहीं है। आजादी के बाद अगर कोई एक राज्य ऐसा है, जहां किसी एक दल को 49 प्रतिशत मत मिला है, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि गुजरात में जनादेश मिला है, 49 प्रतिशत वोट यानी हर दूसरा वोट जनता पार्टी को मिला है। बाईस साल शासन में रहने के बाद फिर से यह पांच साल के लिए जनादेश मिला है।

(1एस/एकेजी पर जारी)

AKG-PK/1S/3.15

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : सभापति महोदय, 1965 के बाद एक भी कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं है, मैं रिकॉर्ड चेक करके आया हूँ, जो 27 साल के लिए शासन में रही हो। फिर भी इसमें जीत दिखाई पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं?

सभापति महोदय, मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ कि तीन नासूर हमारे देश के लोकतंत्र को बहुत समय से डँसे हुए थे - वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण। उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र में से वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को उखाड़ कर फेंक दिया है। हमारे लोकतंत्र को इस अभिशाप से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय, हमने एक पारदर्शी सरकार चलाई है, एक निर्णायक सरकार चलाई है, एक संवेदनशील सरकार चलाई है और भारत के गौरव को स्थापित करने की सरकार साढ़े तीन साल तक चलाई है। इसलिए हमें जनादेश मिला है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने और इस देश के प्रधान मंत्री ने एक विचार देश के सामने रखा था कि इस देश में बारंबार चुनाव के कारण विकास में बाधा आती है, इसलिए चुनाव एक साथ होने चाहिए। अगर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव एक साथ होते हैं, विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे खर्च में भी काफी बचत होगी और बारंबार जो चुनाव आचार संहिता आती है, इसके कारण विकास की बाधा भी समाप्त होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे

कि इससे भाजपा को फायदा होगा, मगर कोई भी जो तत्कालीन स्थिति होती है, वह हमेशा के लिए नहीं होती है। आज हमारा फायदा होता है, कल किसी और का होगा। मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि हम इस पर देश में एक अच्छी बहस छेड़ें, सभी दल इसमें हिस्सा लें और हम एक साथ चुनाव के लिए आगे आएँ।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने एक 'New India' का सपना देखा है, जिसमें कोई बेरोजगार न हो, हर घर में बिजली हो, शुद्ध पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सेवाएँ हों, शिक्षा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को मिल पाए और भारत का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित हो। इस प्रकार के 'New India' के निर्माण के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है, इसलिए उनका धन्यवाद करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe to make his speech seconding the Motion. मित्रो, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा : सर, 'माननीय सदस्य', 'मित्रो' बाहर कहना चाहिए।

श्री सभापति : 'माननीय सदस्य', I stand corrected. माननीय सदस्यो, संख्या बल के आधार पर समय पहले निर्धारित होता है, यह पद्धति शुरू से चल रही है। इस हिसाब से बीजेपी को 2 hours 47 minutes, कांग्रेस को 2 hours 36 minutes और समाजवादी पार्टी को 52 minutes, इस तरह already division हो चुका है। वह मेरे

सामने है। उसमें कुछ गलत दिखाया गया होगा। मेरा सभी पार्टियों से यह कहना है कि आप जितना समय लेना चाहते हैं, उतना लीजिए, रिकॉर्ड आपके पास है, मगर आप आपस में चर्चा करके कि कितने लोगों को बोलना है और उनको कितना समय देना है, वह आप तय करें, तो अच्छा होगा। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। किसी को ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

Number two, यह उनकी maiden speech थी और एक पार्टी के अध्यक्ष यहाँ बोल रहे हैं, वह तो secondary विषय है, main issue यह है कि यह उनकी maiden speech थी। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सहनशील होकर बाकी लोगों को सुनना है।

तीसरा, ...(व्यवधान)... आपने सुना और बाकी लोगों ने व्याख्या भी की। मेरा कहना यह है कि it is not any charity that we heard others. It is the responsibility of everybody that we should hear others, this side and that side. So, please cooperate accordingly. After Dr. Vinay Sahasrabuddhe, we have to go to amendments. Then, the round starts. We will start with the Congress Party, and, then, the other parties. Now, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. आप आपस में चर्चा करके समय तय कीजिए कि किसको कितना बोलना है।

(1टी/एससीएच पर आगे)

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र) : आदरणीय सभापति जी, इस सदन में हमारे आदरणीय सम्मानित सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्रीमान् अमित भाई शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हृदयपूर्वक अनुमोदन करने के लिए यहां खड़ा हूं।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने देश की राजनीति और विशेष रूप से देश की गवर्नेंस के संबंध में बताया कि सरकार किस पद्धति से विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है और कैसे परिवर्तन को मुहैया करने की कोशिश में प्रामाणिकता से लगी हुई है, इसका एक विस्तृत चित्र हमारे सम्मुख रखा है और एक big picture हमारे सामने आई है। जिन बातों को मेरे पूर्व वक्ता ने स्पर्श किया है, उनको पुनः कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर राजनीति शास्त्र और गवर्नेंस के एक छात्र के रूप में जब विगत साढ़े तीन या पौने चार सालों के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के काम को मैं देखता और समझने की कोशिश करता हूं अथवा विश्लेषण करता हूं, तो मेरे जैसे छात्र के सामने तीन बिंदु आते हैं।

सभापति जी, मुझे लगता है कि इस सरकार से आखिरकार आने वाली पीढ़ियां यह चीज़ पूछने ही वाली हैं कि What is your value addition? आपने नया क्या किया, यह प्रश्न कोई भी पूछेगा और लोकतंत्र में यह पूछने का अधिकार भी है।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस सरकार की विशेषताओं के तीन पहलू हैं, जिनका विवरण मैं संक्षेप में आपके सम्मुख रखूंगा। इस सरकार का पहला पहलू है, 'Politics through Inspiration', 'प्रेरणा के आधार पर राजनीति '। यह इसलिए महत्वपूर्ण है,

क्योंकि हमारे देश में विचारधारा की प्रेरणा पर काम करने वाले बहुत कम राजनीतिक दल हैं। दुर्भाग्यवश बहुत सारे दलों की प्रेरणा किसी एक घराने के साथ संबंधित होती है, इसलिए प्रेरणा का जो एक निरंतर वातावरण बनना चाहिए, वह बनता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी बात है, 'Governance through Innovation', 'नवाचार के आधार पर शासकता का परिचय', जिसमें इस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरी बात है, 'Transformation through Implementation.'

सभापति महोदय, हम कहते हैं, the taste of sugar is in eating. ऐसे ही जो नीतियां आती हैं या जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनके परिणाम किस पद्धति से निकल कर आते हैं, इसका परिचय क्रियान्वयन के माध्यम से मिलता है और मैं संक्षेप में इन तीन पहलुओं को आपके सम्मुख उजागर करूंगा।

सभापति महोदय, जब मैं सोचता हूं कि यह सब कैसे हो पाया, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें एक ऐसा जननायक मिला है, जिसका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। किसी को आगे लाना या किसी एक घराने को आगे ले जाना, यह उनकी कार्यसूची का पहलू बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हमारे पास ऐसा एक नेता है, जिनके उद्देश्यों के बारे में, जिनकी प्रेरणा के बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है।

दूसरी बात है, केवल किसी एक समाज विशेष को आगे बढ़ाना। हम देखते हैं कि हमारे कई मान्यवर राजनीतिक नेता अपने-अपने समाज विशेष के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। प्रधान मंत्री हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हुए,

उसी कार्यक्रम को अमल में लाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े हैं, चाहे वह गुजरात में हो या अभी हमारी केन्द्र सरकार का नेतृत्व करते हुए हो। मैं मानता हूं कि देश की राजनीति में और देश का नेतृत्व जो अब तक रहा है, उसमें एक विशेषता इस पहलू की भी है, जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैंने इनोवेशन का जिक्र किया। आज लोग इनोवेट करते हैं, नवाचार से सोचते हैं, नई कल्पनाओं को लड़ाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक ऊर्जा अंदर होती है, कुछ नया करने की एक ललक होती है और ललक होती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं, कुछ अलग पद्धति से पेश आएं। मगर मैं सोच में पड़ गया कि इतनी सारी सरकारें हुईं, इतने सारे प्रधान मंत्री हमारे देश ने देखे और 55 साल तो एक ही दल का शासन हमने देखा, तो क्या इनको इनोवेशंस की कोई पड़ी नहीं थी? इन्होंने नवाचारों का अमल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने out-of-the-box सोच को अपनाया? मुझे लगता है कि जब किसी दल विशेष के *status quo* को मेंटेन करने में एक vested interest बन जाता है, तो innovation से लोग दस कदम दूर रह जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, क्या करना है परिवर्तन करके, सत्ता तो हमारे साथ आनी ही है। लोगों को taken for granted लेते हुए जिन्होंने अपनी राजनीति की, मैं मानता हूं कि उन्होंने इस पद्धति से innovations का सहारा न लेते हुए, जो यथास्थिति थी, जो *status quo* था, उसको ही और अधिक मज़बूत करने की दिशा में अपनी राजीनति और अपने शासन तंत्र को आगे बढ़ाया, जिसके कारण 55 साल के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी रही। सभापति महोदय, कई बार तो मैं अचरज में

पड़ जाता हूं, क्योंकि इन्हीं के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि करप्शन तो पूरे विश्व में है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? (1U/RPM पर जारी)

RPM-SKC/1U/3.25

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत): महोदय, दूसरे एक प्रधान मंत्री ने कहा कि जब एक रुपया खर्च होता है, तो 85 पैसे रास्ते में गायब जाते हैं। बड़े सत्य का साक्षात्कार हुआ, लेकिन बाद में किया क्या? कुछ किया ही नहीं। उसके बाद भी इन दलों के प्रधान मंत्री आए , मगर किया तो कुछ नहीं, क्योंकि करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता, कोई कमिटमेंट वाला विषय ही नहीं था।

सभापति महोदय, अब मैं पुन : एक बार प्रेरणा के विषय पर आता हूं, जो पहला पहलू, मैंने आपके सम्मुख उजागर किया था। प्रेरणा का भी एक संक्रमण होता है। जब लोगों के ध्यान में आता है कि ऊपर बैठे हुए शीर्षस्थ नेतृत्व का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, किसी घराने को आगे बढ़ाने की कवायद नहीं है, किसी समाज विशेष को नेतृत्व करते हुए, जैसे माननीय अमित भाई शाह ने कहा कि 'अविच्छिन्न दिवाकरो', बस हम ही सत्ता में रहें, इस तरह की भावना जब नहीं है, तो मैं मानता हूं कि लोग भी उस प्रेरणा से स्वयं प्रेरित हो जाते हैं।

सभापति महोदय, हमने अभी-अभी देखा, विशेषकर पिछले साल सितम्बर में, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने Smart India Hackathon किया। अब यह Hackathon नई बात नहीं है। विश्व के कई देशों में Hackathon होता रहा है और Hackathon का मतलब यह होता है कि software के माध्यम से बुनियादी और विशेष

रूप से गवर्नमेंट की समस्याओं के कोई समाधान ढूंढ़ना। समाधान ढूंढ़ने के लिए प्रधान मंत्री जी ने और हमारे संबंधित मंत्रालय ने पूरे देश के छात्रों का आह्वान किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ का आह्वान किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 7,530 टीमें बनी थीं। एक टीम में लगभग 5-6 इंजीनियरिंग के होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। इसमें 40 हजार छात्रों ने भाग लिया और 598 समस्याओं के समाधान ढूंढ़ने के लिए सारे छात्र अपना समय और अपनी प्रतिभा लगाते रहे। इसमें 2150 इंस्टीट्यूशन्स के छात्र आए। ये तब होता है, जब उनके ध्यान में आता है कि कोई यदि हम कोई सुझाव देंगे, हम यदि कोई समाधान ढूंढ़ कर निकालेंगे, तो यह सरकार उसका स्वागत करेगी, क्योंकि सरकार का कोई स्वार्थी और केवल दलगत एजेंडा नहीं है।

सभापति महोदय, इसका संक्रमण कैसे होता है ? इसका संक्रमण समाज के अन्यान्य क्षेत्रों में होता है। अभी हमने सुना कि शौचालय की समस्या के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उल्लेख किया। किसी के ध्यान में भी नहीं आया होगा और किसी को यह लगा भी नहीं होगा कि प्रधान मंत्री इस तरह के विषय को भी लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे और उनके भाषण का यह बिन्दु भी बन सकता है, मगर हुआ। हमने कहा था कि सारे सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनेंगे, बनवा दिए। जो कहा सो किया। इसके कारण प्रेरणा का संक्रमण हुआ और हमारे अक्षय कुमार को लगा कि हम 'टॉयलेट' नाम से, प्रेम कहानी की एक फिल्म भी बना सकते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि टॉयलेट जैसे विषय पर, एक कहानी को उसके इर्द-गिर्द गूंथते हुए, एक अच्छी-खासी फिल्म बन सकती है, मूवी

बन सकती है, लेकिन बन गई। अभी 'पैडमैन' नाम की एक मूवी आई है, क्योंकि महिला के स्वास्थ्य का विषय, इस देश के विकास के एजेंडे से हमने जोड़ा है। आप चाहें, तो उपहास कर सकते हैं। यह तो आपका अधिकार है ही और आपने कई बार उपहास किया भी। कभी कहा कि विकास पगला हो गया। भाई, विकास का जिसके लिए महत्व ही नहीं है, वही उसे पगला कहेगा, क्योंकि आपने कभी लोगों को विकास की दिशा देने के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए आपने सोचा कि विकास को बदनाम करो, विकास के बारे में अनाप-शनाप बातें कहो। आपने इसी पद्धति से राजनीति को आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये छोटी-छोटी चीजें भी व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा निर्माण कर सकती हैं और इसके कई उदाहरण हैं।

महोदय, हमने स्मार्ट सिटीज़ का विषय आगे बढ़ाया। अब लोग बोलते हैं कि यह सरकारी कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम जन सहभागिता के आधार पर चल रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस पद्धति से लोग इससे जुड़ रहे हैं and I am not quoting from any book where a report has been published. By and large, the cities organized workshops about smart cities, held talks and blogs, printed newsletters, employed FM radio and local cable channels, held street plays, marathons, बहुत सारे विषय हुए, कहां-कहां हुए, Pune and Sholapur deployed youth associations like *Ganesh Mandals* during *Ganesh Chathurthi* to crowd-source ideas. Pune also organized the Digital Hackathon and Appathon,

conducted a signature campaign where three lakh citizens pledged their support to Pune's Smart City Plan. स्मार्ट सिटी का प्लान, किसी सरकारी बाबू द्वारा बनाया गया प्लान नहीं है। यह लोगों की सहभागिता से बन रहा है। केवल पुणे और शोलापुर की बात नहीं है। भुवनेश्वर में, वहां के छात्रों ने आगे आकर 'हमारा बचपन कैम्पेन' और 'हमारे विश्व की चिन्ता' आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और 'मेरे सपनों का भुवनेश्वर कैसा हो', इस विषय की चर्चा छेड़ी।

(1 डब्ल्यू/पीएसवी पर जारी)

PSV-HK/1W/3.30

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत): यह तब होता है, जब जनता को लगता है कि विकास हमारा साझा एजेंडा है, यह किसी एक व्यक्ति का, किसी एक दल का या किसी एक सरकार का एजेंडा नहीं है। इसलिए यह प्रेरणा का जो संक्रमण हुआ, उसके माध्यम से हम आगे बढ़े। इसमें कई सारी बातें हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहाँ पर हमारी एक माननीय सांसद सम्पतिया उइके जी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र से, मंडला से आती हैं। उनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ब्रीफ बायो वगैरह पढ़ने का बहुत ज्यादा कष्ट भी हम नहीं लेते। अब ये हमारे ही सदन का एक हिस्सा बन जाती हैं। सम्पतिया जी की एक विशेषता है, जो मैं सदन को बताना चाहता हूँ। ये एक ग्राम पंचायत की प्रधान बन कर सामने आईं,

विगत 17 सालों में जिला परिषद् की अध्यक्षा बनीं और ये लगातार तीन-चार बार निर्विरोध चुन कर जिला पंचायत की अध्यक्षा के रूप में आईं। उन्होंने क्या किया? सम्पतिया जी और उनके सहयोगी 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जिन महिलाओं ने अपना विकास करा लिया, जो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो गईं-- राजा साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यह आपके आनन्द का विषय है-- उनमें से 6,000 महिलाओं ने अपने Below Poverty Line Cards सरकार को वापस किये और कहा कि अब हम गरीब नहीं हैं। 'हम गरीब नहीं हैं ', यह कहने के लिए भी ताकत लगती है। 'गरीबी हटाओ' का नारा देना तो आसान होता है, मगर गरीबी से लोगों को यथाशीघ्र मुक्त करना और यह कहना कि 'अब यह उन लोगों को दो, जो वास्तविकता में इसके लिए हकदार हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है। ' यह साधारण बात नहीं है।

ऐसी ही प्रेरणा का संक्रमण हमारे पंजाब के संत सींचेवाल जी हैं। उन्होंने अपनी नदी का उद्धार किया। एक दृष्टि से नदी को साफ रखने का एक बहुत ही असाधारण उदाहरण संत सींचेवाल जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। सींचेवाल जी के पास हमारे गंगा के किनारे के सारे सरपंचों को सरकार के गंगा विभाग ने प्रशिक्षण के लिए भेजा। लोग वहाँ से प्रशिक्षित होकर आये। उस प्रेरणा से अपने गाँव वालों को प्रेरित करते हुए गंगा की सफाई के लिए हमारी सरकार सारे सरपंचों की मदद से, सहयोग से काम कर रही है।

वही बात महिलाओं की है, जो सम्पतिया जी ने किया। अभी एक सरकार ने last year, 7 सितम्बर, 2016 में महिलाओं के e-haat खोले हैं। आपको पता नहीं होगा, मगर कई सारी women entrepreneurs, self-help groups and NGOs इसका उपयोग करते हुए अपनी छोटी-छोटी चीज़ें अब विश्व के बाजार में बेचने के लिए सजग हुए हैं और उस पद्धति से खुद को ढाल भी रहे हैं।

वनवासियों, आदिवासियों के बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती है। इस सरकार ने वनाधिकार के तहत जो पट्टों को वितरित करने की आवश्यकता थी, उसको एक अभियान के रूप में, राज्यों के सहयोग से चलाने की एक मुहिम भी अपनायी है। मनरेगा का उपयोग करते हुए वनवासी, आदिवासी किसानों के खेत-तालाबों का काम भी हो रहा है और अभी-अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एकलव्य विद्यालयों की योजना का इजहार किया है, घोषणा की है, मैं मानता हूँ कि आदिवासी जनजातीय जीवन में भी यह एक अपने आप में एक बड़ा कदम है। उससे निश्चित रूप में आदिवासी, वनवासियों की जो नयी पीढ़ी है, वह और अधिक कारगर बनेगी। मेरे मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, जब-जब विकास की चर्चा होती है, एक competitive spirit आ जाती है। Healthy competition होना भी चाहिए। मगर हम जब भी कुछ कहते हैं, तो सामने बैठे हुए हमारे मित्र बोलते हैं कि यह तो हमने भी शुरू किया था। हमारे मराठी में 'आरम्भशूर' नाम का एक शब्द है कि आरम्भ करना, बाद में छोड़ देना, फॉलो नहीं करना। यह सही है। 2012 में मेरे खयाल से इन्हीं की सरकार ने दलितों के लिए, हमारे

Scheduled Castes भाइयों के लिए एक Venture Capital Fund बनाया था। यह 2012 में बना। इनकी सरकार 2014 तक थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2015 में इस योजना पर कारगर अमल करने की शुरुआत हुई। 200 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि हमने मुहैया की और आज दलित समाज से, Scheduled Castes समाज से कितने सारे उद्यमी इस *Dalit* Venture Capital Fund का उपयोग कर रहे हैं ! समस्याएँ तो रहती हैं। योजना बनाना आसान होता है। जब उसको क्रियान्वयन के धरातल पर लाते हैं, तो समस्याएँ आती हैं। There were many challenges. The first challenge was smooth and speedy delivery of credit which was addressed by instituting a single-window system. The second was to address the lack of equity capital by funding entrepreneurs through a mix of equity, quasi equity and debt instruments. Equity instruments are expected to yield a return of 15 per cent and debt instruments are expected to yield a return of 10 per cent per annum. The third challenge was the very real issue of constraints on providing collateral against loans or debentures which was dealt with by making the assets of the project funded through VCF and promoters' contribution part of the security.

(1एक्स/वीएनके पर जारी)

VNK-DPS/1X/3.35

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत) : जब एक इच्छा-शक्ति होती है, एक राजनीतिक इच्छा-शक्ति होती है, एक political will होती है and when there is a will, there is a way. इस पद्धति से यह सरकार काम करते आई, इसके कारण परिणाम निकल कर आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं innovation की बात कर रहा था। हम कई बार बारीकियों में जाते नहीं और तफसील से बहुत ज्यादा झांक कर देखने का स्वभाव ही नहीं होता, भूल जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये केवल नारे हैं। मगर यह सरकार नवाचार के माध्यम से क्रियान्वयन को और अधिक तगड़ा कर रही है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है Government e-Market, जिसको GeM बोलते हैं। आपको पता होगा और सदन में इतने सारे पुराने मंत्री भी बैठे हैं, वे तो जानते ही हैं कि भारत सरकार हर वर्ष लगभग चार लाख करोड़ रुपए की सामग्री परचेज़ करती है, उसमें टेबल-कुर्सी, फाइल, पेपरवेट से लेकर सारी चीजें होती हैं। अभी तक परचेज़ करने की जो स्थापित पद्धति थी, वह टेंडरिंग की थी और एल-वन, एल-टू आदि सारी बातें हम जानते हैं, इस भाषा का भी हमें परिचय है, मगर इसमें दुनिया के, कम से कम भारत देश के अंदर के सारे उद्यमियों की सहभागिता के लिए कोई अवसर नहीं था, क्योंकि कई बार एक कारटेल जम जाता है, सत्ता के निकट जो होते हैं, उन्हीं को वह अवसर मिल जाता है। सरकार ने इसका भी एक democratization किया और minimum price, maximum ease के सूत्र को अपनाते हुए उसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो, इसकी चिंता की, technology को leverage किया। आज हम देख रहे हैं, जुलाई, 2017 के आंकड़े मेरे

पास हैं, लगभग 9,500 वेंडर्स ने GeM पर खुद को रजिस्टर किया है। अब सरकार 21 हजार प्रोडक्ट्स इन वेंडर्स के माध्यम से ले रही है और 1,370 सेवाओं को भी सरकार इसी माध्यम से अर्जित कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि त्रिपुरा के bamboo की चटाई बनाने वाले या ट्रे बनाने वाले किसी व्यक्ति को भी अपना उत्पाद दिल्ली के गलियारे में बेचने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब इस पद्धति के माध्यम से त्रिपुरा के bamboo की चटाई बनाने वाले या ट्रे बनाने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली के गलियारों में अपनी ट्रे बेचना आसान हो गया है, संभव हो गया है। किसी ने इस पद्धति का शायद सपना भी नहीं देखा होगा और यह हो रहा है।

सभापति महोदय, इसके कारण लगभग 15 से 20 प्रतिशत की बचत हुई है, पहले मार्केट में वह जिस प्राइस पर मिलती थी, अब उससे कम प्राइस पर हम इस पद्धति से खरीददारी की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह सफलता एक उल्लेखनीय सफलता है।

मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय implementation के बारे में है, हमारे क्रियान्वयन के बारे में है। मैं क्रियान्वयन के ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूँ, मगर एक उदाहरण, जो मुझे लगता है कि हम सबको जिसके बारे में गौर करना चाहिए, वह है आधुनिक सूचना तंत्र का प्रशासन के साथ रिश्ता बिठाना, क्योंकि आम आदमी भी, जो अभी स्मार्टफोन यूज़ करता है और न भी यूज़ करता हो, जो एसएमएस भेज सकता है, वह फोन के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी समस्या विश्व के सम्मुख ला सकता है। विशेष रूप से हमारे रेल विभाग ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। मैं

वर्तमान रेल मंत्री और पूर्व रेल मंत्री का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस पद्धति से twitter और फेसबुक पर जो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, उनका संज्ञान लेकर और उनके ऊपर कार्रवाई करने का एक सफल, कारगर और एक प्रभावी तंत्र विकसित किया है, वह सराहनीय है। इसके लिए रेल विभाग अभिनंदन का पात्र है। पूरे देश में लगभग 12,670 गाड़ियां हर रोज चलती हैं और 8,000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन्स हैं। यहां पर जितनी सारी समस्याएं आती हैं, चाहे ट्रेन के डिब्बे में कोई शराब पीकर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की समस्या हो, चाहे कोई महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ सफर कर रही हो और बच्चे को दूध पिलाने के समय अगर उसका दूध खराब हो गया हो, तो उसको दूध कैसे मिलेगा, अगले स्टेशन पर दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह समस्या हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों ने tweet किया और रेल विभाग ने उसका जवाब दिया तथा उनका सहयोग किया। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ, जिसके कारण RailMinIndia, यह जो twitter handle है, उसके followers की संख्या कैसे बढ़ी है। अप्रैल, 2016 में इसके followers की संख्या लगभग 10 लाख थी, दिसम्बर, 2016 में यह 20 लाख हो गई और नवंबर, 2017 में यह बढ़ कर 33 लाख हो गई। इतनी मात्रा में यह बढ़ोतरी हुई है, इसका कारण यह है कि लोगों के बीच एक भरोसा कायम हुआ है कि अगर हम tweet करते हैं, फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं, तो रेल विभाग के संवेदनशील अधिकारी तुरंत उसके बारे में कार्रवाई के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि अब उनको पूछने वाला कोई है। अब तक तो ऐसा था कि हम भी पूछेंगे नहीं, आप भी हमें पूछो मत और फिर जब जनता पूछती

थी, तब जवाब देना पड़ता था, मगर आज यह पूछपरक होती है। अब यह पूछा जाता है कि यह क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतना समय क्यों लगा? मैं मानता हूँ कि इसके कारण प्रशासन तंत्र में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने बाकी भी काफी काम किए हैं, जैसे कोच मित्र योजना है, डीआरडीओ की मदद से बॉयो टायलेट्स बने हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सारे विषयों पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर यह हो पाया है।

(1वाई/एनकेआर-केएसके पर जारी)

NKR-KSK/1Y/3.40

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत) : महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र एन.डी.ए. सरकार का खोजा हुआ नहीं है, बल्कि यह तो पहले से था। 2005, 2008, 2010, 2012 में आपका ही का राज था। आप भी कर सकते थे। मनरेगा के बारे में यहां चर्चा तो बहुत चलती रही और मनरेगा का क्रेडिट भी आप लेते रहे, मगर MNREGA assets का geo-tagging करना, यह काम आपके ज़माने में नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि जैसे ग्रामीण सिंचाई योजना है, प्रधान मंत्री आवास योजना है, भुवन पोर्टल के माध्यम से इन पर निगरानी रखने का जहां तक सवाल है, वह काम इस सरकार ने किया है, जिसके लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। इसका कुछ संदर्भ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया है।

अब अंतिम तीन बिन्दु कहकर, सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक विषय की ओर तो हमारे माननीय पूर्ववक्ता ने इंगित किया है कि पकौड़े बेचना किसी भी तरह गलत काम नहीं कहा जा सकता। उसे लेकर अनेक तरह की बातें

कही गईं और उसकी तुलना भिक्षा मांगने वाले से की गई - मैं समझता हूं कि वह बहुत गलत और बहुत घिनौना स्टेटमेंट था। जब मैंने वह ट्वीट देखा, सुना और पढ़ा तो मैं बहुत उद्वेलित हो गया। मैं जानता हूं कि जिन्होंने पकौड़े बेचे हैं, उन्होंने कम-से-कम अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, self-respect को नहीं बेचा। अपनी self-respect को बेचते हुए, कदम-कदम पर जिन्होंने compromises किए, corruption को सहारा दिया और अनेक गलत बातें की, मैं मानता हूं कि उनसे हमारा पकौड़े बेचने वाला अधिक सम्मान का अधिकारी है। उसके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वह देश में मेहनत-मज़दूरी करने वाला व्यक्ति है। वह किसी भी पद्धति से, किसी appeasement के माध्यम से या किसी व्यक्ति के तले अपनी सेवा समर्पित करके अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि उसके प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए।

जब यहां विकास को नकारने की बात आई, विकास के उपहास की बात आई - ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभाव का भी हम महिमा-मंडन करते आए हैं। अभाव की स्थिति, गरीबी की स्थिति कोई गलत स्थिति है, गरीब के प्रति, अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गरीबी को glorify करें, मगर ऐसा हुआ। इस देश में गरीबी को glorify करते हुए राजनीति करने की कोशिश की गई और लोगों को बताया गया कि गरीब रहना ही ज्यादा अच्छा है। मैं मानता हूं कि देश में एक अपराधजन्य स्थिति बनाई गई, लोगों के मन में निराशा का वातावरण पनपने दिया गया और एक नकारात्मकता का दौर चलाने की कोशिश हुई

और इसी आधार पर अपनी राजनीति को मजबूत करने का माहौल इस देश ने देखा। इसी के चलते, देश में वोट बैंक की राजनीति मुख्य धारा बन गई।

अभी मैं देख रहा था, दो दिन पहले की बात है, ट्रिपल तलाक के बारे में आदरणीय अमितभाई शाह ने अपने भाषण में भी उल्लेख किया और सदन में उस पर चर्चा भी होगी, मगर क्या आज के ज़माने में, महाराष्ट्र में हमीद दलवाई जैसे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, वह भी उनके भाई हैं, एक प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी महाराष्ट्र के एक नेता का यह कहना कि हमारे धर्मग्रन्थ के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है - कौन से विषय को लेकर हम चल रहे हैं ? क्या देश में हम वोट बैंक की politics करेंगे और वह कौन सा धर्म ग्रन्थ है जो कहता है कि महिलाओं को अपमान-भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करना आवश्यक है? मैं नहीं मानता कि कोई धर्म ग्रन्थ ऐसा कहता होगा। हर धर्म ग्रन्थ व्यक्ति की इज्जत करता है, मगर ऐसा statement एक सुलझे हुए नेता की ओर से क्यों आया? इस तरह की वोट बैंक की politics करना, इसके सिवाय दूसरा जिन्दगी में कुछ किया ही नहीं, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई। इसकी जितनी भर्त्सना कड़े-से-कड़े शब्दों में हम करें, मैं मानता हूं कि वह कम है।

सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 55 साल तक जिस दल का राज रहा और आज भी वे आदतें जाती नहीं - Mr. Chairman, Sir, most of the Members on the other benches, unfortunately, are indulging in a crass politics of doubt. As against that, we are working with a politics of

determination. This is a struggle between doubt versus determination, between ridicule versus resoluteness, between fragmentation versus fraternity. मैं मानता हूं कि अंत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे सम्मुख एक प्रेरणा है, एक उद्देश्य है और काम को क्रियान्वयन के आधार पर जनता की रोज़मर्रा की जिन्दगी में परिवर्तन लाना हमारा संकल्प है, हमारी निष्ठा है।

(1Z/DS द्वारा क्रमागत)

DS-GSP/3.45/1Z

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत) : महोदय, मुझे कई बार याद आता है कि आज दुनिया के बहुत सारे जनतांत्रिक देशों में और भारत के बारे में भी कुछ साल पहले यह स्थिति थी कि लोगों को यह लगता था कि इस जनतंत्र ने हमें दिया क्या है। सभापति महोदय, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक उपन्यास है- "ए फेयरवेल टू आर्म्स।" उसका जो नायक है, वह आर्मी का एक जवान है। उसमें एक दृष्टांत यह आता है कि बहुत कड़ाके की ठंड है और वह जवान एक लकड़ी को जला रहा है। उसके आस-पास और दो-तीन लोग बैठे हैं, जो उस लकड़ी के जलाने से उत्पन्न हो रही उष्मा का आनन्द ले रहे हैं। तभी उस नायक के ध्यान में यह आता है कि इस जलती हुई लकड़ी पर कुछ चींटियाँ हैं। वह देखता है कि वे चींटियाँ उस जलती हुई लकड़ी पर एक ओर जाती हैं, तो उन्हें वहाँ अग्नि का जाल दिखाई देता है और जब वे दूसरी ओर जाती हैं, तो वहाँ भी वे देखती हैं कि वहाँ भी अग्नि ही है। उनको देखकर वह नायक कहता है- Like these ants, I also feel that I am trapped. मैं मानता हूँ कि इस देश की जनता को भी कई बार ऐसा

लगा होगा कि we are trapped, क्योंकि जनतंत्र से अलग कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, मगर जनतंत्र मेरी थाली में कुछ परोस भी तो नहीं रहा ! तो जनतंत्र चाहिए भी, मगर जनतंत्र डिलीवर तो नहीं कर रहा! इस अवस्था को पूर्णविराम देते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में what we have given is a delivering democracy. We have established that the democracy also can deliver; we have established that development is the right of every other person, अंत्योदय के विचार से अनुप्रेरित होते हुए । इसलिए सभापति महोदय, इस सरकार के हमारे साथी, जो *तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें, न रहें* - इस भाव से काम कर रहे हैं, एक दृष्टि से उस काम का ही एक reflection माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में है। इसलिए इस सदन को राष्ट्रपति जी के प्रति साधुवाद देना चाहिए, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as I said in the beginning, I would like to repeat again, whoever is speaking either from this side or that side, he should be heard with respect and rapt attention even if you may agree or disagree. Even the Leader of the Opposition is also likely to speak today. Please see to it that during his speech also, all sides may respect each other so that the level of the debate can go up and people can appreciate the standard of the debate in the House. Please keep it in mind.

(**MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is time for moving amendments. There are 324 amendments to the Motion. Now, I am allowing these amendments one by one. Amendment Nos. 1 to 68 and 69 to 75 by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूँः-

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 76 to 77, Ch. Sukhram Singh Yadav; absent. Then, Shrimati Chhaya Verma; absent. Then Amendment Nos. 78 to 81 by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूँः-

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 82 to 90 by Shrimati Chhaya Verma; absent. Then Amendment Nos. 91 to 95 by Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I move:-

91. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the grant of Special Category Status to the residuary State of Andhra Pradesh inspite of the assurance given by the then Prime Minister on the floor of Parliament on 20th February, 2014 and the then Union Cabinet decision on 3rd March, 2014."

92. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the Government's commitments made in Schedule 10 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 including establishing a Railway Zone headquartered at Visakhapatnam, an Integrated Steel Plant at YSR District, a port at Duggirajapatnam etc., in Andhra Pradesh."

93. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the Government's commitment to bear the complete costs of the Polavaram National Project at the current, post-2014, price levels."

94. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the address does not mention about fulfillment of the assurance given to the successor State of Andhra Pradesh that package for backward districts of Rayalaseema and North Andhra region would be given on the lines of Bundelkhand in UP and MP and KBK districts in Odisha, as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014."

95. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to greater political participation of women by securing passage of the Constitutional Amendment Bill for the reservation of seats for women in Parliament and State Legislatures at the earliest."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 96 to 107 by Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवाल (**उत्तर प्रदेश**) **:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 108 to 188 by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I move:-

108. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing Special Development Package/Central Grants for the State of Andhra Pradesh in the backward districts of Rayalaseema and north Coastal Andhra Pradesh."

109. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about giving tax incentives for the State of Andhra Pradesh to compensate revenue deficit in the State."

110. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to expedite national Polavaram multi-purpose project for providing water and electricity to the State of Andhra Pradesh.

111. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to take all necessary measures as enumerated in the 13th Schedule of AP Reorganisation Act for the progress and sustanable development of the successor States."

112. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives, to the successor States to promote industrialization and economic growth in both the States, as provided in the AP Reorganisation Act."

113. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about expanding existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati airports to international standards."

114. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about creation of separate railway zone with the headquarters at Visakhapatnam, as provided in the AP Reorganisation Act."

115. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about waste, polluted water from drains discharged into the major rivers of the country, particularly, the Yamuna, the Ganga, the Godavari, and the Krishna."

116. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about putting an end to economic disparity."

117. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about making polluted cities of the country pollution-free."

118. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need of balanced growth in the country."

119. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about brining appropriate reforms in the present education system and making it employment-oriented."

120. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the formulation of a national level action plan for water conservation."

121. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about formulation of a comprehensive scheme for tackling growing unemployment and to create more employment opportunities in the rural areas."

122. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about formulation of a national level action plan for land conservation in the country."

123. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about improving the quality of programmes being broadcast/telecast by Akashwani and Doordarsahn in the rural parts of the country."

124. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the steep rise in the incidents of murder of old people, women and children and providing proper security in the metropolitan cities."

125. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about formualation of effective scheme for the welfare of landless labourers."

126. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing telecom services on priority basis in the backward and rural areas of the country."

127. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about arresting the steep fall in the ground water level in the country."

128. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the formulation of National Livestock policy."

129. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the development of the tourist spots of the country particular in Andhra Pradesh in order to attract domestic and foreign tourists all the year round."

130. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to bring rational changes in the income-tax structure."

131. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about taking measures for increasing the production of foodgrains, pulses and edible oils in proportion to the increasing population in the country."

132. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the prevalence of fake currency in Indian market which tends to weaken the economical structure of the country."

133. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the increasing pendency of the cases in various courts including High Courts and Supreme Court."

134. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about adopting modern technology for agricultural development in the country."

135. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about adopting new technology in the sugar industry of the country for increasing the production."

136. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on the tendency of dropping-out from the schools by a large number of boys and girls in the primary and middle classes of the schools in the country."

137. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about establishment of agriculture science centres in all the districts of the country."

138. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing loan assistance by re-structuring the loans to be given to the farmers by Nationalised Banks/ Cooperative Banks in view of adverse weather conditions and natural calamities."

139. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about improving industrial production in the country."

140. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to achieving annual export targets."

141. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about checking increasing activities of I.S.I. in the country."

142. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about resolving the border disputes among different states in the country."

143. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about resolving the water disputes among different states in the country."

144. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the necessity of providing drinking water to every village in the country."

145. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about satutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims."

146. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about an effective industrial policy to check migration from rural areas to cities."

147. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to immediate reforms in judicial process to deliver expeditious justice. "

148. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the facilities to be provided for the upliftment of women belonging to the backward and rural areas of the country."

149. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about measures to check brain drain of specialists, technicians, scientists and doctors from the country."

150. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about overcoming the shortage of cold storages for storing vegetables, potatoes, onions and other perishable goods in the country."

151. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the lack of transportation facilities in more than half of the rural areas of the country."

152. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to take steps to protect and provide financial and marketing assistance to small and taditionalindustries in the wake of entry of big multinational companies and big industrial houses."

153. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about launching a computer based education system in the rural areas."

154. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about bringing about necessary reforms for ensuring efficiency, efficacy and accountability in administration."

155. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing sufficient funds for specific programme to encourage girls and women in the fields of sports."

156. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about popularizing sports like Judo and Karate among girls and women for self-defence."

157. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to purchase sophisticated defence equipments in time."

158. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to modernize the fleet and submarines in Indian Navy which witnessed frequent break-downs and failures recently."

159. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing easy access to thefarmers in scientific research particularly in the area of bio-diversity."

160. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about financial assistance to voluntary sports clubs in cities and villages."

161. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing sports facilities to youth through Residents' Welfare Associations."

162. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about playing the conventional role by India in promoting peace, stability and security in international relations."

163. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing security to all important nuclear plants and establishments in the country."

164. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about improving the facilities provided to Central Reserve Police Force and other central security forces."

165. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about streamlining the public administration system across the country."

166. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about filling up the posts of thousands of officers and defence personnel lying vacat in Indian Army, Air Force and Navy."

167. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing good quality mid day meal to the children during recess in the school."

168. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about opening of various monuments/heritage sites for viewing by common public on the line of Taj Mahal, to promote tourism."

169. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about setting up of any regulatory authority for monitoring and regulating the income generated through telecast of sports tournaments."

170. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to formulate Pricing Policy of Drugs due to wide difference in the manufacturing cost of the medicines and their retail prices."

171. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing more funds forScientific and Industrial Research."

172. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about supplying coal according thedemand to the Thermal Power Stations, steel and cement plants throughout the country."

173. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to ban the spurious medicines in the country."

174. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about making Khadi Village Industries Commission more result oriented and productive."

175. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about augmenting domestic production of crude oil to become self-reliant in the filed of crude oil and to decrease the continous import of crude oil."

176. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing adequate storage capacity in public sector of agricultural produce and about promoting creation of storage facilities in private sector."

177. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about setting up an animal husbandary and dairy work research centre in Andhra Pradesh for helping the farmers."

178. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about effectively implementing the technology mission in the field of horticulture."

179. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing loan facility to farmers through cooperative primary banks, rural banks and commercial banks."

180. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing housing facility to mining workers."

181. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about providing sufficient numberof doctors, medical equipments, medicines in ESI hospitals."

182. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing environment and climate change as a compulsory subject at the primary level schooling."

183. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening of residential schools in each development block to promote girl-education at primary school level."

184. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing special assistance to para-military forces like ITBP, CRPF, BSF for purchasing vehicles, modern communication technology and weapons to keep vigil on borders and stop infiltration."

185. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing grants and technical facilities for the articles made by the Indian craftsmen/artisans through the cottage and small-industries of the country and encouraging the export of produced goods."

186. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about steep rise in the prices of petrol and diesel, which is increased marginally on day to day basis."

187. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about enacting appropriate legislation to ensure major role of local panchayats in the preparation of dvelopment schemes for the rural development of the country."

188. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating appropriate policy to meet the challenge of deteriorating political, economic and social situation in the country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 189 to 193 by Dr. Pradeep Kumar Balmuchu; absent. Then, Amendment Nos. 194 to 217 by Shri Kiranmay Nanda.

SHRI KIRANMAY NANDA (UTTAR PRADESH): Sir, I move:-

194. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about atrocities on Dalits and Minorities in various States, which cause loss of human life and property."

195. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about attacks on Minority in the name of Cow protection."

196. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about sharp increase in unemployment caused by demonetization and GST."

197. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about increasing incidence of sexual attacks on girls specially on minor girls."

198. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about sharp hike in the prices on general commodities by which common man is affected."

199. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of farmers suicide due to sharp increase in their financial debts."

200. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about increasing problems of potato growers."

201. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about uncontrolled air and water pollution in the NCR and other cities in the country."

202. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of Cancer and Diabetes in the country."

203. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about eradication of child labour from the country."

204. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about continuous increase of Petrol prices under new Petrol pricing Policy."

205. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about out come of dream project of Prime Minister about Sansad Aadarsh Gram Yojana."

206. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about usefulness of Toilets in absence of piped water supply."

207. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that the Address is to mention how to improve quality of education in Government Primary Schools, which makes foundation of nation".

208. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about sharp decrease in ground water level, in spite of rain water harvesting schemes being already in implementation".

209. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about very sharp increase of communal and religious introlerance".

210. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about in the digital transactions and threat of cyber crimes to digital world".

211. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about dying Small Scale Industry of our country due to dumping policy of China to kill our Industrial growth".

212. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about our tense relations with China and Pakistan".

213. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of Bank's NPAs, affecting financial health of Indian Banking System".

214. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the concrete measures taken so far for doubling of farmers income".

215. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about Waste (Kachara) management and processing etc."

216. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about continuous devaluation of Indian Rupee as compared to US Dollar".

217. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about amount of black money collected so far by Government through demonetization".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 218 to 231 by Shri T.K. Rangarajan, Shri C.P. Narayanan, Shri K. Somaprasad and Shri K.K. Ragesh. Yes, Shri T.K. Rangarajan.

SHRI T.K. RANGARAJAN (**TAMIL NADU**): Sir, I move:

218. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities, including petrol and diesel."
219. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country and also the failure of the Government in providing employment to the unemployed as promised earlier."
220. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the growing intolerance manifesting in the violence against writer and cultural activities and spread of communal polarization in the country."
221. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the agrarian crisis and increasing suicide of farmers in the country due to faulty policy of the Government."

222. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address fails to mention about the growing incidents of mob lynching, for increase the recent brutal killing of a migrant labourer in Rajasamand, Rajasthan and another in Gujarat."

223. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address fails to mention about the increasing attacks and atrocities on dalits, tribals and Adivasis in the country."

224. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address fails to mention about the lack of transparency in the selection of judges as well as the accountability of judiciary towards the people."

225. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address fails to mention about the natural calamities including Okhi cyclone and subsequent loss of lives and properties particularly in Kerala, Tamil Nadu, Lakshadweep and other parts of the country and failure of the Government to provide adequate compensation to the affected States."

226. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the guidelines for the Government for liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) and portfolio management."

227. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people for food under Public

Distribution System in the country even after implementation of the Food Security Act."

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

229. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to allot 6 per cent of GDP to education as well as 5 per cent of GDP to health sector."

230. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to bridge the gap of demand and supply of electricity and under utilisation of the hydro electric power potential of various rivers in Kerala."

231. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about Justice Ranganath Misra Commission report which recommended 10% reservation for Muslims and 5% for other minorities, based on socially and economically backward criteria."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 232 to 259 by Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (**TAMIL NADU**): Sir, I move:

232. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not reiterating India's commitment to pursue an independent foregin policy."

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not refer to the continuous attack on the ideals enshrined in the Constitution of the country."

234. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not refer to the increasing attack on the constitutional and democratic rights of the citizens."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not refer to the issue of judicial accountability and to the prevailing crisis in judiciary in general and higher judiciary in particular."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of Dalit communities in the country."

237. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the attempts to curtail trade union rights of the workers in the name of ease of doing business."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmes committing suicide in the country."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector banks and the need to take stringent measures to recover the defaulted loans from the willful defaulters particularly in the corporate sector."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the continuous slow down in the growth rate of economy."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note to attract the continuous decline in India's export during the last few years."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the delay in passing the legislation on Reservation for women in the Parliament and State Assemblies."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education, particularly at the higher level in the country."

247. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education for the common people."

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the increasing incidents of crime against women and children in the country."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the failure of the government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the need to recognize the 'scheme workers' numbering a crore in the country mostly women working under various schemes of the Government of India, as workers, as per the recommendations of the 45th Indian Labour Conference making them eligible for PF, ESI and other social security benefits."

252. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the increasing attacks on the trible people in the country, particularly in Chhattisgarh."

253. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the fact decision of demonetization of currency notes of Rs. 500 and Rs. 1000 denominations pushed the economy as well as the common people into a distressful condition."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not take note of the fact that certain right wing forces in the country are trying to destory the secular-democratic fabric of the country by attacking the Universities, all educational and cultural institutions, freedom of speech, right to dissent, minorities, dalits, tribals and progressive activists."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the diversion of allocations made for sub-plans for Tribals and SC/ST."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the increasing number of derailments in Railways due to deterioration of safety standards and ignoring the recommendations of various reports on accidents in the Railways."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the continued protest of the Ex-service men demanding full implementation of the One-Rank-One Pension (OROP)."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the thousands of villages still remain without electricity in the country."

259. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the disinvestment of the public sector undertakings thereby weakening the fundamentals of the economy."

(Followed by SK/2A)

SK-MCM/3.50/2A

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment No. 260 by Shri Narain Dass Gupta; absent.

Now, Amendment Nos. 261 to 268 by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN (KARNATAKA): Sir, I move:-

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address fails to mention about the dignity and pride that a Muslim woman enjoys under Shariah Law and has therefore, undermined the status of Muslim women."

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address does not mention about the condition of the 85% women from religions other Muslim in the country, who are facing daily harassment and are fighting legal battles after their husbands have deserted them for years without any maintenance and without even giving divorce, and the Government's policy about such women."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that the Address fails to mention that the relaxation given to the women above 45 years of age to perform Haj Pilgrimage in a group of four is as per the new guidelines and exemptions given by the

Saudi Government from the ensuing Haj season and that the Indian Government has adopted the new Saudi policy."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take notice of the plight of the Muslim women who are socially and educationally backward and have negligible representation in Govt. Services."

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why subsidy on Haj had to be abolished with immediate effect and the amount of subsidy Govt. was paying."

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take notice of the increased incidents of Communal violence's in the country."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the alarming financial health of the Indian Banks due to increase in NPA's of the Public and Private sector Banks which according to finance ministry stands at Rs. 7,73,974 crore and Rs. 1,02,808 crore, respectively as on 30.09.2017."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why the Petrol and Diesel prices were not reduced proportionately in spite of a huge fall in the oil prices at the international market."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 269 to 272 by Shri K.K. Ragesh.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I move:-

269. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the growing attack on freedom of speech and expression as manifested in the henious killings of Gauri Lankesh, Kalburgi, Narender Dhabolkar, Govind Pansare, etc."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the drastic cut in subsidies including fertilizers, LPG, Diesel etc."

271. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the growing NPA in public sector banks and the government's decision to write off the NPA as book adjustment."

272. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—
"but regret that there is no mention in the Address about the injustice by State Bank of India in imposing fine on poor account holders who are unable to maintain monthly average balance."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 273 to 297 by Shri Motilal Vora.

SHRI MOTILAL VORA (CHHATTISGARH): Sir, I move:-

273. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not mention about the halting of businesses and difficulties being faced by the common masses due to sealing in Delhi."

274. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the military structures being set up by China in Doklam."

275. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the communal riots that took place in Kasganj, Uttar Pradesh on Republic Day."

276. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the ongoing dispute between Punjab and Haryana Governments on SYL Canal and redressal of difficulties being faced by farmers in irrigating the land."

277. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to stop the migration from villages as farming is increasingly becoming unprofitable."

278. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any plan for stabilizing or increasing the area of steadily shrinking land holdings of cultivable land."

279. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for addressing the lack of adequate transport facilities in rural areas."

280. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for ensuring 24 hours availability of electricity across the country."

281. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken with regard to employment opportunities for the educated citizens of the country who have crossed the stipulated age for getting Government jobs."

282. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken to ensure availability of work for the labourers of unorganised sectors throughout the year."

283. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the obligation of realizing charges by the hospitals and test centres for the medical treatment of common citizen at the rate fixed by the C.G.H.S. with a view to providing medical treatments to all the citizens of country."

284. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to strengthen the storage of foodgrains in Government godowns and for construction of new godowns.

285. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about raising the standards of education in Government schools so that parents' preference toward private school diminishes."

286. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to strengthen the internal security of the country and to make it strong and fool proof."

287. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to stop ponzi schemes which usurp the hard earned money of

the citizens by misleading them or bringing them in the purview of law of the country."

288. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to bring the rising pollution in the metro cities of the country including Delhi as per the norms."

289. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for putting a complete check on adulteration of food items."

290. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention making adulteration free pure milk available to the children in the country."

291. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for filling up the various posts of teachers lying vacant on large scale in the education sector of the country."

292. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about concrete steps to be taken to wipe out naxalism from the country."

293. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for an early solution of incidents of arrest of Indian fishermen by neighbouring countries of Sri Lanka and Pakistan who unknowingly cross the country waters while going for fishing."

294. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for appointment on vacant posts in higher judiciary by which justice can be given to citizens on time by early disposal of cases."

295. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about steps to be taken to bring back the land area in Indian territory that was annexed by China."

296. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to the provide equal education to all the children of the country."

297. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps to be taken ever increasing gap between the rich and the poor of the country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 298 to 324 by Shri Husain Dalwai.

SHRI HUSAIN DALWAI (MAHARASHTRA): Sir, I move:-

298. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about rising intolerence in the form of attacks on minority communities by vigilante groups and failure of government to protect these communities."

299. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about attacks on *Dalits* in states like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh."

300. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the inability of the Government to ensure protection of women from sexual and physical abuse, to utilise the Nirbhaya Fund and to criminalise marital rape."

301. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government in addressing concerns of the transgender community in the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 and extending reservation benefits to them."

302. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of interest of the government to introduce the Women's Reservation Bill on a priority basis."

303. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rising Non-Performing Assets (NPAs), failure of Public Sector Banks to recover these NPAs even though banks go about collecting charges from account holders who are unable to maintain minimum balance."

304. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the inability of the Government to take adequate steps for welfare of unorganized sector workers."

305. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to reduce dependence of farmers on informal sources of capital and instead increase access to formal institutionalized source of capital and the need to encourage organised retail to prevent market dominance as

well as allow easy access to land through leasing and contract farming models."

306. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fall in prices of crops as well as climate change induced temperature and rainfall ariability affecting farmer's earnings leading to rise in farmer suicides."

307. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about rising income inequality in India."

308. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government to adequately address the issue of manual scavenging despite the enactment of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation act."

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the issue of low adoption rate of technology, in rural areas due to lack of technology enablers, which is making schemes related to e-health, e-governance, e-education and e-commerce ineffective."

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the problem of malnutrition faced by India, which ranks 100 out of 119 countries on the Global Hunger Index."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that while providing Constitutional status to the National Commission of Backward Classes, there are apprehensions over diluting the existing powers of the Commission."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the attempts being made to dilute the protection provided to tribals under the Forest Rights Act, through several measures, for instance by delay for the formulation of rules under the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the mistreatment of activists protesting against increasing height of Sardar Sarovar Dam and displacement of several people without adoption of adequate rehabilitation measures."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about attacks on free speech and the inability of the Government to protect journalists, RTI activists, whistleblowers who stand for free speech."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the introduction of electoral funds will adversely affect transparency in election funding and strengthen the business political nexus.

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of steps taken to ensure preparedness and build capacity to deal with natural disasters of many states suffered immense loss of life and property due to Cyclone Ockhi, one of the most intense cyclones in the country, due to their unpreparedness."

317. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to stabilize the situation in Jammu and Kashmir and the

lack of clarity with respect to the role of representative of the Indian Government appointed to conduct talks with different stakeholders."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that India is one of the four worst performing countries (ranked 177 out of 180 countries) in the Environmental Performance Index 2018."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the increasing number of road accidents and inadequate measures to upgrade quality of roads and incomplete and slow construction work on NH-66, connecting Mumbai to Goa, which has caused several road accidents killing many people every year."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that anganwadi workers are not receiving timely payment of wages."

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the issues faced due to linkage of Aadhaar, including security issues like bank frauds, authentication failures leading to exclusion deaths and disruptions in availability of entitlements under various welfare schemes."

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the increasing train accidents, poor railway infrastructure and inadequate investment is safety as in a short period of 1 August and 30 November, 2017, 30 train accidents killed 35 people and injured more than 180 people resulting in the highest death toll from train derailments in 2016-17."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about high rates of GST on basic necessities like sanitary napkins and assistance devices for persons with disabilities."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the insufficient investment in welfare of fishermen to create necessary infrastructure and protect their rights and interests."

MR DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Motion and the Amendments moved are open for discussion.

The questions were proposed.

(Ends)

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, में यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और उनको धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देता हूं माननीय अमित शाह जी को, पहला भाषण इनका हुआ, मेडन स्पीच हुई। इसलिए हम लोगों ने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना, लेकिन उनके भाषण में सरदार पटेल जी का नाम नहीं आया, यह देखकर, सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि दो-तीन चीजों की तथा अन्य और बातों की 2014 के इलेक्शन में बहुत चर्चा हुई थी। हम लोगों पर आरोप लगा था कि हम सरदार पटेल का आदर नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा मैं यह कहूंगा कि जब कभी भी हमने गांधी जी और नेहरू जी का नाम लिया है, साथ में सरदार पटेल जी का नाम जरूर बचपन से लिया है, बल्कि मौलाना आज़ाद का भी नाम लिया है। इन तीनों-चारों का नाम इकट्ठा लेते आए हैं। सुभाष चन्द्र

बोस को एक अलग तरीके से हम और भी मरहम देते आए हैं कि उन्होंने भारत की सीमाओं से लेकर और अम्बेडकर जी का उनका कांस्टीट्यूशन बनाने में जो रोल रहा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कुछ अंदर रोल करते थे, कुछ देश से बाहर करते थे कांस्टीट्यूशन वाले, उनका अलग किरदार रहा। बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, बहुत है। सब राजनीति दल, उनके नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन जिस बुनियाद की आधार पर 2014 में यह सरकार बनी थी, 2013 के आखिरी कुछ महीनों से माननीय प्रधान मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैम्पेन कमेटी के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के उम्मीदवार हो गए थे, तो जो सबसे बड़ा आरोप यू0पी0ए0 सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था, आज आपकी ही सरकार, बहुत खुशी हुई कि आज हमारी सरकार में अगर हमको कोर्ट अदालतें और अटॉर्नी जनरल शायद उन आरोपों से मुक्त कराते तो हम पर जरूर यह आरोप लगता कि हमसे प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर सी0बी0आई0 कोर्ट ने निर्णय लिया 2जी का, तो हमारे खिलाफ जो हिमालय का पहाड़ खड़ा किया गया था, सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम लिया गया था, सैकड़ों और हजारों सभाओं में, शुक्र है कि आपकी ही सरकार में उस सी0बी0आई0 के जज ने उन तमाम दोषियों को बरी कर दिया।

(2B/SC पर जारी)

SC-YSR/3.55/2B

श्री गुलाम नबी आज़ाद (क्रमागत) : तो आपने जो इमारत खड़ी की थी, जो रेत की दीवार, रेत का हिमालय आपने बनाया था, वह चार-पांच साल तक तो चला, लेकिन

गांधी जी हमेशा कहते थे कि सत्य की विजय होती है - आखिरकार सच की विजय हुई। बोफोर्स पर कई सरकारें बनीं। 1986-87 से लेकर, बल्कि शायद भारत के इतिहास में पहली दफा हुआ कि लेफ्ट, राइट और सेंटर सब कांग्रेस के खिलाफ एक हो गए। मैं उस समय यूपी का इंचार्ज था और देख रहा था कि सब पोलिटिकल पार्टीज़ एक फोरम से भाषण कर रही थीं। भगवान माननीय वी.पी.सिंह साहब को स्वर्ग में जगह दे, वे जेब में एक कागज़ लिए हर वक्त मीटिंग में कहते थे, यह मेरी जेब में कागज़ है, आप हमारी सरकार बना दो और मैं दूसरे दिन नाम बता दूंगा। आप सब लोगों ने मिलकर उनकी मदद की, वे प्रधान मंत्री बने, लेकिन उनके जीवन-काल में वह कागज़ उनकी ऊपर वाली जेब से नहीं निकला। तब से लेकर आज तक कई प्रधान मंत्री बने, वे बोफोर्स की आग पर अपनी रोटियां सेंकते रहे। मैं भगवान का लाख-लाख शुक्र करता हूं कि आपकी सरकार ने ही, आपके ही Attorney General ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि इस पर और कोई सबूत नहीं है, इतने सालों से हम इस पर लगे हुए हैं। इसलिए वह बेबुनियाद था, फिर भी आप करेंगे।..(व्यवधान)..

कुछ माननीय सदस्य : कर दिया।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आपने कर दिया। आप उस नाम पर कितनी सरकारें बनाएंगे जिसमें उसके बाद इतने प्रधान मंत्री बने और विपक्ष की कई सरकारें बनीं। माननीय बीजेपी के अध्यक्ष ने यहां बताया कि माननीय मोदी साहब ने तीन चीज़ों से देश को मुक्त किया। आपने वंशवाद की बात की। ज़ाहिर है, आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं,

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 29-30 साल से उनका कोई प्रधान मंत्री नहीं है। जब प्रधान मंत्री नहीं है तो आपने निजात किसको दिलायी है?

श्री आनन्द शर्मा : मंत्री भी नहीं है।..(व्यवधान)..

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मंत्री भी नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, प्रधान मंत्री भी नहीं हैं। इससे पहले भी 1977 में आपकी ही पार्टी थी। उससे पहले भी दो प्रधान मंत्री बन गए, बल्कि तीन प्रधान मंत्री बन गए - लालबहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के थे, लेकिन दो गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री भी बन गए। तो ऐसा कहने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देता, यह जो डर उनके जीवित रहते था, अब कुछ लीडर्स ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन अब उनके बच्चों से भी आपको रात को नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? वह डर बना रहे।

आपने जातिवाद के बारे में कहा। मैं कहता हूं कि जातिवाद तो एक बहुत पुरानी चीज़ थी - आज़ादी से पहले थी। आज तो देश का बंटवारा हो गया है, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर में बंटवारा हो गया है। आज कोई किसी के साथ नहीं है। धर्मों का बंटवारा हुआ, जातियों का बंटवारा हुआ, एक-एक धर्म के कई बंटवारे हुए - मैं बाद में जब उन बातों पर आऊंगा, तब उनका उल्लेख करूंगा।

तुष्टिकरण के बारे में कहा गया। आप तुष्टिकरण के संबंध में जिस तबके की बात करते थे, आज दूसरी तरह का तुष्टिकरण है। आज पार्टी का तुष्टिकरण है और एक ही पार्टी चला रही है, उसी की बात सुनी जा रही है।

(2सी-जीएस पर जारी)